MRA AN UNIVA The Gazette of India

असाबारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (l)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 557]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 2, 2001/कार्तिक 11, 1923

No. 557] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 2, 2001/KARTIKA 11, 1923

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 नवम्बर, 2001

2/2001-स्वापक नियंत्रण-1

सा.का.नि. 819(अ).— स्वापक औषधि तथा मनः प्रभावी द्रव्य नियमावली, 1985 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, पहली अक्तूबर, 2001 से आरम्भ होने वाले और 30 सितम्बर, 2002 को समाप्त होने वाले अफीम फसल वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार की ओर से अफीम पोस्त की खेती के लिए नीचे विनिर्दिष्ट लाइसेंसों की मंजूरी हेतु सामान्य शर्ते अधिसूचित करती है:—

प्रस्तावना

भारत सरकार --

अफीम के अनिवार्य औषधीय उपयोग पर विचार करते हुए,

अफीम पोस्त की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस कच्ची सामग्री के एक मात्र वैध सप्लायर के रूप में अपनी भूमिका को समझते हुए,

औषध के अवैध व्यापार, औषध के दुरूपयोग और स्वापक औषधि जनित उग्रवाद की रोकथाम करने की आवश्यकता के प्रति संजगता दर्शाते हुए,

3423 GI/2001

एतद्द्वारा फसल दर्ष 2002 के लिए अफीम की खेती के लिए लाइसेंस मंजूर करने हेतु निम्नलिखित सामान्य शर्तें निर्धारित करती है :--

1. खेती करने के स्थान

किसी भी ऐसे भूखंड में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिया जा सकता है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए ।

2. खेती के लिए पात्रता

केवल वही किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2001 के दौरान मध्यप्रदेश, राजस्थान के राज्यों में औसतन कम से कम 52 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर अथवा उत्तर प्रदेश में 44 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर उपज प्रस्तुत की हो, लाइसेंस के पात्र होंगे।

तथापि, उपर्युक्त सीमा निम्नलिखित श्रेणियों के किसानों पर लागू नहीं होगी:

- (i) जिन्होंने सरकारी देखरेख में फसल वर्ष 2001 के दौरान पूरी पोस्त खेती की जुताई की हो;
- (ii) जिनकी लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2001 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो; अथवा
- (iii) जिन्होंने पिछले किसी भी वर्ष में पोस्त की खेती की हो और अनुवर्ती वर्ष में लाइसेंस के लिए पात्र हों, किन्तु, किसी कारणवश स्वेच्छा से लाइसेंस प्राप्त न किया हो अथवा, जिन्होंने उसने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश पोस्त की खेती न की हो ।

3. लाइसेंस की शर्तें

किसी भी किसान को तब तक लाइसेंस मंजूर नहीं किया जाएगा जब तक वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा न करता हो :--

(क) उसने फसल वर्ष 2001 के दौरान पोस्त की खेती के लिए लाइसेंसशुदा और नापे गए क्षेत्र से अधिक क्षेत्र में खेती न की हो ;

- (ख) उसने कभी भी अफीम पोस्त की अवैध खेती न की हो अथवा स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अंतर्गत उस पर किसी अपराध के लिए सक्षम न्यायालय में आरोप नहीं लगाया गया हो;
- (ग) फसल वर्ष 2001 के दौरान उसने केन्द्रीय नार्कोटिक्स ब्यूरो द्वारा किसानों को जारी किन्ही विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन न किया हो अथवा अपनी अफीम में कोई मिलावट न की हो ;
- (घ) जिन किसानों ने फसल वर्ष 2001 के दौरान लाइसेंसशुदा क्षेत्र से कम क्षेत्र में अफीम पोस्त की खेती की थी और /अथवा जिन्होंने 10 आरी से कम भूखण्ड में अफीम पोस्त की खेती की थी किन्तु न्यूनतम अईक उपज दी थी और जो लाइसेंसिंग नीति, 2002 की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं उन्हें फसल वर्ष 2002 के लिए लाइसेंस दिया जाएगा।

4. अधिकतम क्षेत्र

कृषि के लिए अलग से क्षेत्र 20 आरी का होगा। लाइसेंसधारकों को उस संपूर्ण क्षेत्र में खेती करनी होगी जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है। यदि कोई लाइसेंसधारक उपर्युक्त शर्तों का पालन नहीं करता है तो वह आगामी फसल वर्षों के लिए अफीम पोस्त की खेती के लाइसेंस का हकदार नहीं होगा।

कोई भी किसान एक से अधिक प्लाट में अफीम पोस्त बो सकता है परन्तु प्रत्येक प्लाट 10 आरी से कम नहीं होना चाहिए ।

जपर बताई गई बातों के बावजूद, सरकार अफीम की खेती वाले राज्यों में अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए कृषि अनुसंधान संस्थानों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों को 20 आरी से अधिक क्षेत्र आबंदित कर सकती है।

5. माफी योग्य सीमा

अतिरिक्त खेती के संबंध में माफी योग्य सीमा लाइसेंसशुदा क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

6. फसल वर्ष 2003 में न्यूनतम अर्हक उपज के लिए पूर्व चेतावनी

अनुवर्ती वर्ष में अफीम लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र बनने हेतु फसल वर्ष 2002 के दौरान मध्यप्रदेश और राजस्थान में प्रति हैक्टेयर 53 किलोग्राम और उत्तर प्रदेश में प्रति हैक्टेयर 45 किलोग्राम की न्यूनतम अर्हकारी उपज अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए।

7. विविध:

- (i) इन अनुदेशों से नारकोंटिक्स आयुक्त/नार्कोटिक्स उपायुक्त के किसी भी लाइसेंस को जारी करने/उसे रोकने के अधिकार को कोई क्षित नहीं पहुंचती जब भी वह स्वापक ओषधि तथा मनःप्रभावी द्रव्य पदार्थ अधिनियम, 1985 के उपबंधों और उसके बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसा करना ठीक समझता हो।
- (ii) लाइसेंस इस शर्त पर दिया जाएगा कि किसी भी खेत को संयुक्त वैध अफीम पोस्त सर्वेक्षण (संवैवअवपोवसव) के प्रयोजनार्थ अधिगृहीत किया जा सकता है जिसे सरकार द्वारा अथवा सरकार द्वारा विशिष्ट संस्था अथवा एजेंसी के साथ सहयोग करके किया जाए। जिस किसान के खेतों को संवववअवपोवसव के लिए चुना जाएगा उसको अगले वर्ष लाईसेंस मंजूर करने पर विचार किया जाएगा चाहे उसने फसल वर्ष 2002 के दौरान कितनी ही उपज प्रस्तुत क्यों न की हो, और वह अन्यथा पात्र हो।
- (iii) जो किसान सान्द्रक पोस्त भूसी (सा. पो. भू.) की खेती करना चाहेंगे वे अगले वर्ष के लाइसेंस के लिए पात्र होंगे, यदि वे अन्यथा पात्र होंगे ।
- (iv) अपर वर्णित अफीम की मात्रा का कारखाना विश्लेषणों के आधार पर 70 डिग्री शुद्धता के आधार पर हिसाब लगाया जाएगा ।
- (v) उपर्युक्त किसी बात के होते हुए भी सरकार को उन गांवों में अफीम की खेती के लिए अनुमित को वापस लेने का अधिकार है जहां किसी भी समय खेती के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 2 हेक्टेयर अथवा सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य सीमा से कम हो।

[सं. 2/2001/फा. सं. 616/5/2001-स्वापक नियंत्रण-1] अशोक चक्रवर्ती, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd November, 2001

2/2001-Narcotics Control-I

G.S.R. 819(E).—In pursuance of rule 8 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the general conditions for grant of licences specified below for cultivation of opium poppy on account of the Central Government during the Opium crop year commencing on the 1st day of October, 2001 and ending with the 30th day of September, 2002.

PREAMBLE

The Government of India-

CONSIDERING the indispensable medicinal use of opium,

RECOGNISING its role as the sole licit supplier of this raw material to meet requirements of opiates.

CONSCIOUS of the necessity to prevent and combat drug trafficking, drug abuse and narco-terrorism.

HEREBY lays down the following general conditions for grant of licences for opium cultivation for the crop year 2002

1. PLACES OF CULTIVATION

Poppy cultivation may be licensed in any tract as may be notified in this behalf by the Central Government.

2. ELIGIBILITY FOR CULTIVATION

Only those cultivators who have tendered an average yield of not less than 52 kgs./hectare in the States of Madhya Pradesh, Rajasthan and 44 kgs./hectare in Uttar Pradesh during the crop year 2001 shall be eligible for licences.

However, the above limit shall not be applicable to the cultivators of the following categories:

(I) Who ploughed back their entire poppy cultivation during the crop year 2001 under the supervision of Government,

- (II) Whose appeal against refusal of Licence has been allowed after the last date of settlement in the crop year 2001; or
- (III) Who cultivated poppy in any previous year and were eligible for licence in the following year, but did not voluntarily obtain the licence for any reason, or who after having obtained licence for the following crop year, did not cultivate poppy due to any reason.

3. CONDITIONS OF LICENCE

No cultivator shall be granted licence unless he/she satisfies that:

- (a) He/She did not exceed the area licenced and measured for poppy cultivation during the crop year 2001;
- (b) He/She did not at any time resort to illicit cultivation of opium poppy and was not charged in the competent court for any offence under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder;
- (c) During the crop year 2001 he/she did not violate any departmental instructions issued by the Central Bureau of Narcotics to the cultivators or had not adulterated his/her opium;
- (d) Those cultivators who had cultivated oplum poppy during the crop year 2001 in less area than the area licensed and/or who cultivated opium poppy in a plot of less than 10 ares but tendered the required MQY and fulfill other conditions of the Lincencing Policy 2002, will be given licences for the crop year 2002.

4. MAXIMUM AREA

Individual area for cultivation shall be 20 ares only. The licensees shall sow in the entire area for which license has been issued, Failure to follow the above conditions shall disentitle the licensees for license of opium poppy cultivation for future crop years.

A cultivator can sow opium poppy in more than one plot but each plot should not be less than 10 ares.

Notwithstanding anything stated above, the Government may allot an area of more than 20 ares to the agricultural research institutes or Agriculture University in opium states for research purposes.

5. CONDONABLE LIMIT

The condonable limit in respect of excess cultivation shall not exceed 5% of the licenced area.

6. FOREWARNING FOR MINIMUM QUALIFYING YIELD IN THE CROP YEAR 2003

A minimum qualifying yield of 53 kg/hectare in Madhya Pradesh and Rajasthan and 45 kg/hectare in Uttar Pradesh must be tendered during the crop year 2002 to become eligible for opium licence in the following year.

7. MISCELLANEOUS

- (i) These instructions are without prejudice to the right of the Narcotics Commissioner/Deputy Narcotics Commissioner to issue/withhold a licence whenever it is deemed proper so to do in accordance with the provisions of the Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Act, 1985 and the Rules made thereunder.
- (ii) The licence will be subject to the condition that any field may be taken over for Joint Licit Opium Poppy Survey (JLOPS) that may be conducted by the Government or by the Government in collaboration with specialised institution or agency. The cultivator whose field is selected for JLOPS shall be considered for granting licence next year irrespective of the yield tendered by him during the crop year 2002, if otherwise eligible.
- (iii) The cultivators opting for cultivation of opium poppy for the Concentrated Poppy Straw (CPS) shall be eligible for licence next year, if otherwise eligible.
- (iv) The quantity of opium mentioned above will be calculated at 70° consistence, on factory analysis.
- (.V) Notwithstanding anything stated above, the Government reserves the right to withdraw permission for opium cultivation in such villages where the total area under cultivation, at any time, falls below 2 hectares or any other limit prescribed by the Government.

[No. 2/2001/F. No. 616/5/2001-Narcotics Control-I] ASHOK CHAKRABARTI, Under Secv.